THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) The petroleum products are divided into two broad categories viz. the price administered products and free trade products. The major products like MS, HSD, Kerosene, LPG, Furnace Oil, LSHS, Naphtha, Bitumen and ATF etc. are under the price-administered category for which the ex-storage point prices are fixed by the Government. Other products like Lube Base Oil and Lubricants, Benzene, Toulene, Raw Petroleum Coke etc. are in the free trade category for which the Oil companies are free to fix the selling price on market considerations but pool adjustments are allowed upto the refinery stage only. About 90% of total volume of the petroleum products fall under price-administered category.

रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

3579. **श्री रामजीलाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस कनेक्शनों की राज्य-वार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्य-वार कितने लोगों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और उनमें से कितने लोगों को उनके पंजीकरण के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए है;

(ग) सरकार 31 मार्च, 1997 तक पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालु): (क) 1.4.95, 1.4.96 और 1.1.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा नीचे किया गया है:

तारीख	प्रतीक्षा सूची (लाख)
01.04.95	118
01.04.96	133
01.01.97	142

(ख) 1993-94 से 1995-96 के दौरान आरम्भ किए गए नए नामांकन का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	नया एल पी जी नामांकन (लाख)
1993-94	13.6
1994-95	22.9
1995-96	20.5

(ग) और (घ) नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में चरणबद्ध पद्धति से जारी किए जाते हैं। खाना बनाने की धरेलू गैस के रूप में एल पी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और रियायती मूल्य के कारण इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप नए एल पी जी कनेक्शनों के लिए बड़ी प्रतीक्षा सूची बन गई है। यह मांग एल पी जी के स्वदेशी उत्पादन से एल पी जी की उपलब्धता और संभावित आयातों से अधिक है और इसलिए एल पी जी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर नई नामांकन योजनाएं तैयार की जाती हैं।

देश में आगामी वर्षों में एल पी जी की उपलब्धता बढ़ाकर नए त्वरित एल पी जी नामांकन आरम्भ करने की योजनाएं बनाई गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरम्भ नए नामांकन का राज्यवार ब्यौरा नीचे विवरण में है।

विवरण

एल॰पी॰जी॰ नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा

(आंकड़े हजार में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	100.8	176.1	131.3
अरुणाचल प्रदेश	5.4	7.1	5.2
असम	27.2	45.3	32.2
बिहार	48.5	105.0	46.1
गोआ	6.7	8.4	8.0
गुजरात	57.7	109.8	77.1
हरियाणा	44.4	65.1	47.2
हिमाचल प्रदेश	52.2	48.2	116.3
जम्मू और कश्मीर	32.3	37.4	79.8
कर्नाटक	88.0	119.8	102.5
केरल	85.0	104.2	75.8
मध्य प्रदेश	52.3	104.5	72.6
महाराष्ट्र	168.8	350.9	261.8
मणिपुर	4.2	6.1	6.5
मेघालय	3.4	5.7	7.2
मिजोरम	7.5	6.5	8.8
नागालैण्ड	3.3	3.7	4.2
उड़ीसा	23.0	80.4	29.6
पंजाब	52.4	100.0	79.1
राजस्थान	56.7	73.0	78.2
सिक्किम	1.9	3.3	8.8
तमिलनाडु	94.8	173.0	129.0
त्रिपुरा	2.9	5.4	2.2
उत्तर प्रदेश	185.3	281.0	430.4
पश्चिम बंगाल	72.2	140.8	108.7
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार	2.0	4.3	0.2

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
चंडीगढ़	7.4	13.8	6.5
दादर और नागर हवेली	0.2	0.6	0.2
दिल्ली	93.6	129.0	96.8
दमन और द्वीयू	0.4	0.8	0.2
लक्ष्यद्वीप	0.2	0.3	0.5
पांडिचेरी	1.0	3.9	3.0

Funds from Commercial Banks for import of petroleum products by IOC

3580. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that IOC is contemplating to import petroleum products after tapping funds from Commercial Banks in the absence of Budgetary support;

(b) whether it is going to be a one time emergency measure; and

(c) whether this route was adopted in the past also to overcome such a situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) Indian Oil Corporation, being the sole canalising agent for the import of crude oil and major petroleum products has always been resorting to commercial borrowings for financing oil imports into the country. For this purpose IOC does not enjoy any form of budgetary support from the Government.

Non-allotment of land to LPG distributors by DDA

3581. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the three oil companies had offered LPG distributorships to individuals in different parts of Delhi under open category in December, 1994;

(b) if so, the names of the allottees, area-wise and company-wise;

(c) whether these allotments were made by the companies in consultation with Delhi Development Authority, while drawing market plan for 1993-94;

(d) whether it is a fact that no plot of land has been allotted to any of the allottees by DDA after lapse of more than 27 months;

(e) if so, whether Government proposed to find out the reasons for the non-allotment;

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) Based on the recommendations of the Oil Selection Board (Delhi), only IOC had issued LOI under Open category for two LPG distributorships in Delhi in December, 1994, in favour of Shri